अमेरिकन वैस्ट क्लाइमेंट चेंज से बहुत अधिक प्रभावित है। यहां के बिगड़ते इकोसिस्टम को पुनः बहाल करने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने सुझाव दिया है कि जंगल में भेड़ियों और ऊदबिलाव (बीवर्स) को बसाया जाए। उनका कहना है कि, ये जीव मूलभूत इकोलॉजिकल प्रक्रिया को पुनः बहाल करने में मदद करेंगे। शोध के सहलेखक, ओरेगॉन स्टेट युनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ फॉरैस्ट्री के स्कॉलर, क्रिस्टोफर वुल्फ ने कहा, ''हम लोग अमेरिकन वैस्ट के संकटों, जैसे भारी सूखा और हीटवेव, जंगल की आग, जैवविविधता में कमी, पानी की कमी, आदि को लेकर बहुत चिंतित थे हमने महसूस किया कि, जंगल में भेड़ियों और ऊदबिलाव को बसाकर किसी हद तक इन समस्याओं को संबोधित किया जा सकता है, जिसके कई फायदे हो सकते हैं। बीस वैज्ञानिकों की इस टीम ने अपने शोध पत्र में फैडरल रिज़र्व एरिया का नैटवर्क स्थापित करने का सुझाव दिया। उनका प्रस्ताव है कि कुछ फैडरल भूभागों में मवेशियों की चराई रोककर वहाँ ग्रे वुल्फ तथा नॉर्थ अमेरिकन बीवर की आबादी को बसाया जाना चाहिए। क्रिस्ट्रोफर वुल्फ कहते हैं कि, छोटे-छोटे बांध बनाने की प्रक्रिया में बीवर्स की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, जैसे पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, नदी तट को सुधारना, जिससे नदी तट हरे-भरे रहें। इनमें ना केवल विभिन्न प्रजातियों को सुरक्षित आवास मिल सकता है बल्कि इससे कार्बन उत्सर्जन कम करके अन्ततोगत्वा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता हैं। इसी प्रकार ग्रे वुल्फ के भी कई लाभ हैं, वे स्थानीय, खुरवाले स्तनपायी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर सकते हैं।

'गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश में पायलट मुख्यमंत्री बन जाएं तो हमें अगले चुनाव में कोई नहीं हरा सकता'

मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में एस.सी. आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी बैरवा ने कहा

- **इधर जयपुर में पायलट समर्थक विधायक-बोले- पोस्टर-होर्डिंग हटाए जा सकते हैं, लेकिन दिल में बस चुके पायलट को कैसे हटाएंगे।**
- **वेद सोलंकी बोले- सचिन पायलट की लोकप्रियता से विरोधी घबराए, पोस्टर-होर्डिंग हटाने के आदेश 3 सितंबर को ही जारी कर दिये थे।**

जयपुर, 6 सितम्बर (का.प्र.)। सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर एक ओर जहां उनके समर्थकों की भीड़ उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के नारे लगा रही थी तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में एक बार फिर यह मांग उठी कि अशोक गहलोत पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व संभाले और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं पायलट के पोस्टरों को हटाने को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। पायलट समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने इशारों-इशारों में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ''सचिन पायलट के पोस्टर-होर्डिंग तो हटाए जा सकते हैं, लेकिन जिनके दिलों में पालयट बस चुके हैं, उन्हें कैसे हटाऐंगे।''

मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में राजस्थान एससी आयोग के अध्यक्ष और विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व पद ग्रहण करने की सलाह देते हुए कहा कि आलाकमान यह चाहता है। अलग-अलग क्षेत्रों से उनके नाम की सहमति भी आ रही है। ऐसे में उनको राष्ट्रीय नेतृत्व करना चाहिए। बैरवा ने कहा कि ''गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश में पायलट जैसा मुख्यमंत्री बन जाए तो हमें अगले चुनाव में कोई नहीं हरा सकता।''

उन्होंने कहा कि गहलोत पुराने, सर्वमान्य नेता हैं। च ाण ने भी कहा है कि गहलोत से कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब अंदर कुछ न कुछ चल रहा है। अब प्रमोशन हो रहा है। हमारे पुराने लीडर को वहां जाना चाहिए। हालांकि, उनको ही तय करना चाहिए कि क्या करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री रहे हैं, यूथ लीडर हैं। उनके साथ जनभावना है, लेकिन फैसला आलाकमान को करना है।

दूसरी ओर वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि ''आज जिस तरह से समर्थकों का जनसैलाब उमड़ा है, वह आलाकमान के लिए भी मैसेज है कि राजस्थान की जनता, महिलाएं और खासतौर से राजस्थान का युवा, किसे अपना नेतृत्वकर्ता बनाना चाहते हैं। बिना किसी खर्चे के, बिना किसी गाड़ी-घोड़े के, यह लाखों की संख्या में लोगों का जनसैलाब है, जो यह बता रहा है कि अब वक्त आ गया है कि आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन पर विचार करे।''

सोलंकी ने कहा कि सचिन पायलट की लोकप्रियता से विरोधी इतने घबरा गए हैं कि सिविल लाइन क्षेत्र में पोस्टर-होर्डिंग हटाने के आदेश 3 सितंबर को ही जारी कर दिए गए। यह दर्शाता है कि विरोधियों में किस कदर घबराहट है। उन्होंने कहा कि प्रसाशनिक स्तर पर लिखित में आदेश बिना किसी इशारे के नहीं होते हैं।पोस्टर-होर्डिंग तो हटा सकते हैं, लेकिन जिनके दिलों में पायलट बस चुके हैं, उन्हें कैसे हटाएंगे। सोलंकी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि आलाकमान देखे कि किसी व्यक्ति के पास बिना पद के ये जनसैलाब साथ है तो पद होने पर क्या हो सकता है। सोलंकी ने कहा कि वैसे आलाकमान सब देख रहा है।

सरकारी नोटिस के बावजूद बन गई चार मंजिला अवैध इमारत

कार्रवाई के बजाय उपायुक्त ने चुप्पी साधी

- **जगतपुरा में हाउसिंग बोर्ड के डिजाइन टाइप को तोड़कर बनाई गई अवैध बिल्डिंग, सड़क पर बालकनी निकाल किया कब्जा।**
- **ग्रेटर निगम की जगतपुरा ज़ोन उपायुक्त ममता नागर ने 29 अगस्त को नोटिस थमाकर अवैध निर्माण हटाने को कहा था, भूखंड मालिक धड़ल्ले से निर्माण कार्य पूरा करने में जुटा।**

- कार्यालय संवाददाता -

जयपुर, 6 सितम्बर। राजधानी जयपुर में नगर निगम के अफसरों की शह से धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। भूखंड पर निर्माण की अधिकृत स्वीकृति मिले बिना ही निर्माण हो रहे हैं फिर भी निर्माण जारी है और भवन निर्माण संबंधी नियमों की खुली अवहेलना हो रही है, यहां तक कि सैटबैक भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मिलीभगत का आलम कुछ ऐसा है कि अधिकारी भूखंड मालिक को सिर्फ नोटिस थमा कर अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी तो दे देते हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधकर बैठ जाते हैं।

ऐसा ही एक वाकया ग्रेटर निगम के जगतपुरा जोन में सामने आया है। प्रताप नगर में कॉर्नर भूखंड 174/33 पर हाउसिंग बोर्ड द्वारा बना कर दिए गए ''टाइप डिजाइन'' की अनदेखी कर भूखंड मालिक ने ज़ीरो सेटबैक देकर बेसमेंट समेत चार मंजिला इमारत खड़ी कर ली। यहां तक कि सरकारी सड़क पर भी बालकनी निकालकर आरसीसी डाल दी।

जोन उपायुक्त ममता नागर ने गत 29 अगस्त को भूखंड मालिक झाबरमल चौधरी को नोटिस थमाया और तुरंत अवैध निर्माण हटाने के लिए कहा। इस नोटिस के जरिए भूखंड मालिक से निर्माण की स्वीकृति और स्वामित्व दस्तावेज 3 दिन में मांगे थे। साथ ही चेतावनी भी दी थी कि अगर निर्माण स्वीकृति व अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो एक तरफा कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण को हटा दिया जाएगा।

करीब सप्ताह भर पहले जारी इस नोटिस के बाद जगतपुरा जोन के अधिकारी जैसे यहां कार्रवाई करना ही भूल गए और यहां निर्माण कार्य जारी रही।

खुद उपायुक्त ममता नागर ने स्वीकार किया कि जैसे ही उन्हें इस अवैध निर्माण की शिकायत मिली तो उन्होंने तुरंत भूखंड मालिक को नोटिस जारी करवा दिया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस बारे में वह कोई जवाब नहीं दे पाई।

अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी के वी.सी. की नियुक्ति को कोर्ट में चुनौती

- **अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी के वर्तमान वी.सी. विधि स्नातक भी नहीं हैं और राज्य सरकार द्वारा पारित 2019 के कानून में एक गैर विधि स्नातक भी लॉ युनिवर्सिटी का वी.सी. हो सकता है।**
- **याचिकाकर्ता का कहना है कि जबकि केन्द्र में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे एक गैर विधि स्नातक को लॉ विश्वविद्यालय का वी.सी. नियुक्त किया जा सकता है, केवल राज्य के कानून में यह असाधारण प्रावधान है।**

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 6 सितंबर। राजस्थान हाई कोर्ट में भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के प्रथम वी.सी. की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में लम्बी बहस के बाद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव ने बुधवार को भी सुनवाई जारी रखने के आदेश दिये हैं।

इस मामले में याचिकाकर्ता प्रोफेसर के.बी. अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया पेश हुए थे। इस मामले में राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर और प्रिंसिपल तथा बार काउन्सिल ऑफ इंडिया, राजस्थान बार काउन्सिल और यू.जी.सी. को पक्षकार बनाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि भीमराव अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी, जयपुर एक्ट 2019, में राज्य सरकार ने कॉलेज के चांसलर को ऐसे वी.सी. को नियुक्त करने का अधिकार दिया है जो जरूरी नहीं है कि विधि स्नातक हो। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि केन्द्र सरकार की संस्था यू.जी.सी. के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत लॉ युनिवर्सिटी का वी.सी. कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो विधि स्नातक न हो। याचिका में कहा गया है कि अम्बेडकर लॉ युनिवर्सिटी के वर्तमान वी.सी. विधि स्नातक न होने के कारण, वी.सी. पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी जनहित याचिका में गलत तरीके से नियुक्ति प्राप्त वी.सी. या किसी अन्य पद के अधिकारी को चुनौती दे सकता है, पर कानून को जनहित याचिका में चुनौती नहीं दे सकता।

वही यू.जी.सी. की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने भी यही कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका की आड़ में कानून को चुनौती दी है, जो गलत है। उन्होंने आगे कहा कि कानून की वैधता का प्रश्न नहीं है क्योंकि कानून के मुताबिक ही वी.सी. को चयनित किया गया है।

जिस पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव के नेतृत्व में खण्डपीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार के यू.जी.सी. कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक गैर विधि स्नातक किसी लॉ युनिवर्सिटी का वी.सी. हो सकता है। अदालत ने आगे कहा कि राज्य सरकार का कानून भी केन्द्र सरकार के कानून की तर्ज पर ही बना है परन्तु इसमें कुछ अन्य प्रावधान हैं। अदालत ने कहा कि वह इस मामले को गंभीर मानती है और कल भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी।

केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनका संकेत इस तरफ था कि दो शीर्ष अरबपतियों- गौतम अडानी तथा मुकेश अंबानी की सुरक्षा के लिये सी.आई.एस.एफ. की तैनाती की गई है। यह अलग बात है कि अपनी सुरक्षा पर होने वाला खर्च वे स्वयं ही वहन करते हैं। अभी हाल ही में, 1 सितम्बर से सी.आई.एस.एफ. को यहाँ केशव कुंज में बन रहे आर.एस.एस. मुख्यालय तथा उदासीन आश्रम, जहाँ आर.एस.एस. अपना काम-काज करती है, की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है।

'सहकार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व केन्द्र शासित प्रदेशों कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के प्रतिनिधि होंगे।

नई नीति ''सहकार से समृद्धि'' तक की सोच पर आधारित होगी। यह नया प्रारूप देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा। सहकारिता पर आधारित आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा।

पेशे से चार्टर्ड एकाउंटैंट सुरेश प्रभू की भारत के सहकारी आंदोलन में गहरी रूचि ही है वे पूर्व में सारस्वत सहकारी बैंक के चेयरमैन तथा नैशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे हैं।

दिल्ली में प्र.मंत्री शेख हसीना का विरोध

नई दिल्ली, 6 सितंबर (वार्ता)। बंगलादेश में हिन्दुओं एवं बौद्धों पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों एवं जनसंहार से क्षुब्ध हिन्दू संघर्ष समिति, प्रवासी बंगियो समाज एवं ऑल इंडिया रिफ्यूजी फ्रंट ने बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख़ हसीना के भारत दौरे के विरोध में मंगलवार को यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने 'शेख़ हसीना शर्म करो', 'अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो' के नारे भी लगाये।

नीतीश की सद्भावना...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बात चर्चा का रूप ले चुकी है कि कुमार के पक्ष में अभी तक ऐसी कोई ठोस चीज नहीं है जो उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी या भाजपा के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत या प्रदर्शित कर रही हो। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों की जबरदस्त जीत के प्रथम प्रवाह एवं जुनून में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्वयं को विपक्षी एकता अभियान में उतार दिया था तथा उन्होंने मुम्बई और दिल्ली की यात्राएं करके, शरद पवार सहित, विपक्ष के दिग्गज नेताओं के साथ मीटिंग की थी। पिछले महीनों में, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव भी पूरे देश में घूमे हैं तथा वे यह घोषणा भी कर चुके हैं कि उनका इरादा राष्ट्रीय राजनीति में कूदने का है।

विपक्षी एकता के प्रयासों के सफल न होने के दो कारण हैं। एक, विपक्षी खेमा इस बात को लेकर दुविधा में है कि कांग्रेस को साथ लिया जाये या नहीं। दूसरा, विपक्षी दल गैर-भाजपा विपक्षी खेमे में किसी ''भारतीय मॉडल'' का ढाँचा सृजित करने या प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं।

नीतीश कुमार राजनैतिक रूप से कमजोर हो चुके तथा दोषपूर्ण भले ही दिखाई दें, लेकिन विपक्षी खेमे में एकजुटता लाने वाले अन्य लोगों की अपेक्षा वे कुछ बेहतर स्थिति में जरूर हैं। चूँकि वे भाजपा के साथ, वे करीब डेढ़ दशक कार्य कर चुके हैं तथा उसे नजदीकी से देख चुके हैं, इसलिये वे भाजपा-रणनीतिकारों की सोच को बेहतर समझते हैं तथा संभवत: उसकी काट करने वाली प्रभावी रणनीति के बारे में सोच सकते हैं। यह बात हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के बारे में खासतौर से कही जा सकती है। ममता या के.सी.आर. की तुलना में, एक समन्वयक के रूप में कुमार की स्वीकार्यता की ज्यादा संभावना है, विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में ऐसी संभावना भले ही नहीं हो। येचुरी के साथ हुई मीटिंग के बाद, कुमार ने इस बात को दोहराया कि वे प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने वाले नेता की भूमिका में आने की न तो आकांक्षा रखते हैं और न वे इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जे.डी.यू. कार्यकर्ता जो पोस्टर एवं बैनर लगा रहे हैं, उनमें कुमार को 2024 में दिल्ली के सिंहासन का मुख्य चुनौती देने वाले नेता के रूप में प्रस्तुत एवं घोषित किया जा रहा है।

कोटपूतली नगर परिषद से जवाब तलब

- **हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें कहा है कि नगर परिषद ने कई मकान व दुकान बिना नोटिस दिये, बिना मुआवजा दिये और बिना आपत्ति सुने ही तोड़ दिए थे।**
- **याचिकाकर्ता का कहना है कि, नगर परिषद के अधिकारियों ने हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए तोड़-फोड़ की कार्यवाही को अंजाम दिया था।**

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 6 सितंबर। राजस्थान हाई कोर्ट में कोटपूतली नगर परिषद द्वारा सरदार विद्यालय रोड को चौड़ा करने की आड़ में लोगों के घर व दुकान बिना नोटिस और मुआवजा दिये तोड़ने के संबंध में कल कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव के नेतृत्व में गठित खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता गोविन्द नारायण शर्मा ने इस मामले में याचिका दायर की थी और अदालत को कहा था कि, कोटपूतली नगर परिषद ने उनका व अन्य कई नागरिकों का घर व दुकान बिना नोटिस दिये, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार भूमि अवाप्त करे बिना ही तोड़-फोड़ करने की कार्यवाही की थी।

याचिकाकर्ता का कहना है कि नगर परिषद ने हाई कोर्ट के 25 फरवरी को दिये गये आदेश का उल्लंघन किया है, जिसके तहत नगर परिषद के पुराने नोटिस रद्द कर दिये गये थे और साथ ही नगर परिषद को आदेश दिये थे कि वह एक माह में सभी भू-मालिकों और दुकानदारों की आपत्ति सुनकर ही आगे की कार्यवाही की कानूनी प्रक्रिया के अनुसार करे। गत माह की 27 तारीख को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव ने नगर परिषद के अधिकारियों से जवाब तलब किया, जिसकी सुनवाई बुधवार को है।

चुनाव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की ओर से एडवोकेट प्रशान्त भूषण ने पी.आई.एल. के पक्ष में दलीलें दीं। याचिका में मांग की गई है कि, भविष्य की नियुक्तियों के लिए स्वतंत्र कोलीजियम या सलैक्शन कमेटी का गठित की जाए। उन्होंने सी.बी.आई. डायरैक्टर और लोकपाल की नियुक्तियों के उदाहरण दिए, जिसमें विपक्ष के नेता तथा जुडिशिएरी की राय भी शामिल होती है। पी.आई.एल. में दावा किया गया है कि, इलैक्शन कमीशन की वर्तमान नियुक्तियाँ अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) तथा 324 (2) तथा संविधान के मूल लक्षणों का उल्लंघन करती हैं। याचिका में कहा गया है कि, अनुच्छेद 324 (2) में स्पष्ट कहा गया है कि, सी.ई.सी., और ई.सी. की नियुक्तियों के संबंध में न्यायसंगत, स्पष्ट और वाजिब कानून बनाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।

गिरगिटों का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। इसमें किसी बात से बिल्कुल ही विपरीत रूख अख्तियार करना शामिल है जो पहले उन्होंने कभी दावे के साथ कही थी। उनके चुनावी अभियान की शुरूआत भी अपेक्षाकृत अनिश्चित थी, जिसमें कई बार अपने शब्दों को वापस लिया गया।

विदेश मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन पर सबसे हानिकारक टिप्पणी उनके रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव ने की थी, जिन्होंने उनके साथ अपनी मुलाकात को ''किसी बहरे के साथ बातचीत'' की संज्ञा दी थी। उन्होंने सुना लेकिन गौर से नहीं सुना। उन्होंने अपनी टिप्पणियों से फ्रांस के राष्ट्रपति जैसे ब्रिटेन के मित्रों को भी अलग-थलग कर दिया था।

प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के लिए हुए चुनावी अभियान में भी अपनी सार्वजकि चर्चाओं में उनकी पूर्व तैयारी स्पष्ट रूप से ऋषि सुनक से कमतर की, जिन्हें कंज़रवेटिव पॉलीटिकल फिगर्स में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था।

जैसा कि टीकाकारों ने व्यापक रूप से बताया, लिज़ ट्रस टी.वी. डिबेट्स या डायलॉग्स के सार्वजनिक परीक्षण के पक्ष में नहीं थीं, लेकिन ब्रिटेन की अधिकांश जनता, बूढ़े लोगें और कम शिक्षित वर्ग ने उन्हें ऋषि सुनक की तुलना में अधिक स्वीकार्य पाया।

ऑक्सफोर्ड में पॉलिटिक्स, फिलोसॉफी एण्ड इकोनामिक्स की डिग्री या पी.पी.ई. के लिए अध्ययरत रहने के दौरान वे एक लिबरल डैमोक्रेट थी।

पी.पी.ई. एक ऐसा कोर्स है जिसका अध्ययन प्राय: ऐसे लोग करते हैं जिनमें अन्य श्रेणी का विद्यार्थी बनने की कोई स्पष्ट इच्छाशक्ति अथवा योग्यता नहीं होती। अपने समय में वे ब्रिटेन के यूरोपीयन यूनियन से बाहर निकलने की कटु आलोचक थी।

वे ब्रिटेन के खुली अर्थव्यवस्था की विचारधारा रखने के खिलाफ हैं। उन्होंने ब्रिटेन के आयातों पर टिप्पणी करके अपनी कैम्पेन शुरू की। उन्होंने कहा- ''हम हमारा दो तिहाई चीज़ आयात'' करते हैं, फिर एक लम्बे विराम के बाद कहा कि यह एक बेइज्जती है। इस प्रकार से वे फ्री ट्रेड के विचार से पूर्णतया सहमत नहीं थी।

एक बार उन्होंने अनुरोध किया था कि ब्रिटेन में योग्यता को आकर्षित करने के लिए अप्रवासन कानून अधिक उदार होने चाहिए, लेकिन अब उन्होंने वादा किया है कि वे ब्रिटेन में इमीग्रेशन कंट्रोल करने के लिए पुराने कानूनों को बदल देंगी।

कंज़रवेटिव पार्टी की पूर्वब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रैचर उनकी रोल मॉडल हैं, बताया जाता है कि वे उन्हीं के जैसे कपड़े पहनती हैं और सार्वजनिक जीवन में उनकी नकल करती हैं।

राजनीतिक गिरगिटों के पास इन दिनों पूर्ण नियंत्रण है, लेकिन लगता है कि ब्रिटेन के राजनेताओं ने अपने पूर्व उपनिवेश के चालाक नेताओं के हाल ही में कोई एक या दो उदाहरण ले लिए हैं।

'मैं किसी का पोता, बेटा, भाई, किसी का...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

होती नजर नहीं आई।

सादुलशहर के पूर्व विधायक और श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संतोष सहारण तो बधाई देने के लिए सुबह 6:30 बजे ही पायलट निवास पर पहुंच गए।

बात सिर्फ भीड़ ज्यादा होने की नहीं थी, बल्कि इस बार भीड़ में उत्साह बहुत जबरदस्त नजर आया। कोई ढोल की थाप पर नाचता गाता आ रहा था, तो कोई जबरदस्त नारेबाजी कर रहा था। वहीं अलग-अलग नेताओं के समर्थक भी अपने नेता को कंधों पर बिठाकर उस स्थान पर ला रहे थे जहां सचिन पायलट खड़े होकर लोगों की बधाइयां स्वीकार कर रहे थे।

इस दौरान समर्थकों ने सचिन पायलट को उपहार स्वरूप हल, तीर कमान, बाजरे के सिक्के, तलवार, भीमराव अंबेडकर, श्री कृष्ण, देवी माँ तथा हनुमान जी सहित देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां बड़ी संख्या में भेंट कीं।

इस बार पहले से ही ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं के बीच सचिन पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में जयपुर आने वाले हैं और यह अनुमान सही भी निकला जब सुबह 8:00 बजे से शुरू हुआ लोगों का कारवां 2:00 बजे तक निरंतर चलता रहा। ऐसा भी नहीं है कि, सिर्फ गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों से लोग आए हों, बल्कि, राजस्थान के दूरदराज, डूंगरपुर, जालौर सांचौर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, और शेखावाटी से भी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम सचिन पायलट को बधाई देने सिविल लाइन्स पहुंचा।

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट 7 सितंबर को 45 साल के हो जाएंगे। लेकिन 6 सितंबर, यानी जन्मदिन से एक दिन पहले ही सचिन पायलट समर्थकों ने जयपुर में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं, सचिन पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने 21 विधायक और कई निगम बोर्ड आयोगों के अध्यक्ष भी पहुंचे।

सचिन पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने वाले मंत्री-विधायकों में विजेंद्र ओला, हेमाराम चौधरी, मुरारी मीणा, अमर सिंह जाटव, सुरेश मोदी, हरीश मीणा, राकेश पारीक, पीआर मीणा, रामनिवास गावड़िया, जीआर खटाना, मुकेश भाकर, इंद्राज गुर्जर, दीपेंद्र सिंह शेखावत और वेद प्रकाश सोलंकी सहित गहलोत कैंप के 7 विधायक, इंदिरा मीणा, गंगा देवी, गिर्राज सिंह मलिंगा, प्रशांत बैरवा, वीरेंद्र सिंह चौधरी, ओम प्रकाश हुड़ला और सुरेश टांक प्रमुख हैं। साथ ही विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह भी बधाई देने पहुंचे।

वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर और कुलदीप इंदौरा भी सचिन पायलट को बधाई देने जयपुर आए। इनके अलावा बोर्ड निगमों के अध्यक्षों में गोपाल सिंह ईडवा, महेश शर्मा, ब्रजकिशोर शर्मा, अग्रवाल महासभा की चेयर पर्सन शशि गुप्ता, भाजपा सरकार में बोर्ड के चेयरमैन रहे सलावत खां तथा पूर्व मंत्री विधायकों में नसीम अख्तर इंसाफ, महेंद्र मीणा, पूर्व जिला प्रमुख गीता खटाना,राकेश बोयत सहित पीसीसी पदाधिकारियों में प्रशांत सहदेव शर्मा एआईसीसी सदस्य राजेश चौधरी, सुरेश चौधरी, सचिव शोभा सोलंकी,अजमेर के पूर्व महापौर कमल बाकोलिया, जयपुर लोकसभा प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल, श्रीगंगानगर के नेता अशोक चांडक मुख्य रूप से शामिल थे।

स्टालिन कोई कसर नहीं..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चली जाएगी, डी.एम.के. सुप्रीमो ने अपने दीर्घकालिक सहयोगी के प्रति दृढ़ समर्थन व्यक्त किया है। ऐसा करके, स्टालिन तमिलनाडु में भी अपने निजी हितों का संरक्षण कर रहे हैं, जहाँ भाजपा के प्रति मतदाताओं की एक खास किस्म की नापसंदगी दिखाई देती है और इस नापसंदगी का कारण यह है कि द्रविड़ पार्टियाँ ''उत्तर भारत की इस हिन्दी पार्टी'' के खिलाफ वर्षों से जबरदस्त दुष्प्रचार करती आ रही हैं।

एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राजनैतिक मुखिया की ओर से आ रहे समर्थन के इस प्रबल संदेश से कांग्रेस को भी निश्चित रूप से कुछ राहत मिली होगी क्योंकि टी.एम.सी. तथा आप जैसे कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों की ओर से तो कांग्रेस के लिए अपमानजनक बातें की जा रही हैं। हो-हल्ला ही मिल रहा है। प्रसंगवश बता दें कि स्टालिन ने टी.एम.सी. तथा आप से भी बातचीत की है लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक कांग्रेस की भावनाओं का भी ख्याल रखा है तथा उसके गठबंधन को समर्थन देने का पुनः आश्वासन दिया है।

इसके अलावा, स्टालिन का सार्वजनिक प्रदर्शन अर्थात् उनका कांग्रेस एवं राहुल गांधी के समर्थन से कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मदद मिलेगी, उससे कहीं ज्यादा मदद तमिलनाडु में डी.एम.के. को मिलेगी। इसके अलावा, स्टालिन के समर्थन से एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल (कांग्रेस) को यह संतोष मिलेगा कि उसका एक ऐसा भी मित्र दल है, जो खुलकर उसके साथ है, जबकि अन्य क्षेत्रीय दल उसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं।

यहाँ यह याद दिलाना प्रासंगिक होगा कि 2019 के आम चुनावों से पहले, 2018 में ही, यू.पी.ए. के प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में राहुल गांधी का नाम सबसे पहले प्रस्तावित करने वाले स्टालिन ही थे।

दरअसल, तमिलनाडु में वे कांग्रेस के प्रति जितनी ज्यादा नजदीकी प्रदर्शित करते हैं, उतनी ही उनकी भाजपा-विरोधी छवि मजबूत होती है तथा राज्य में उन्हें इसका लाभ मिलता है। भाजपा का प्रबल हिन्दी-समर्थक रूख तथा जबरदस्त एवं आक्रामक हिन्दुत्व का रूख ऐसी चीजें हैं जिनका तमिलनाडु में भाजपा को उतना चुनावी लाभ नहीं मिलता, जितना उसे देश के अन्य हिस्सों में मिलता है।

वस्तुत: तमिलनाडु के लोगों की नजर इस चीज पर है कि भाजपा कितनी आक्रामकता के साथ हिन्दुत्व एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। डी.एम.के. की ओर से, इसके प्रतिकार में, उतना ही बल्कि और भी ज्यादा आक्रामक भाजपा विरोधी रूख सामने आ रहा है। इससे यह बात समझ में आ जाती है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री राजनैतिक रूप से भाजपा-नेतृत्व से क्यों टकराते रहते हैं लेकिन इसके साथ ही वे केन्द्र के साथ काम-काज संबंधी सौहार्दपूर्ण बनाये रखते हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908